VOL. IV—NO. 5.

# THE BIHAR LEGISLATIVE ASSEMBLY DEBATES 1948.

*Wednesday, the 25th February, 1948.*

**Proceedings of the Bihar Legislative Assembly assembled under the provisions of the Government of India Act, 1935.**

The Assembly met in the Assembly Chamber at Patna on Wednesday the 25th February, 1948at 11 A.M., the Hon'ble the Speaker, Mr. Vindhyeshvwari Prasada Varma, in the Chair.

## QUESTIONS AND ANSWERS.

CONFISCATED CLOTH LYING UNDISPOSED AT BHAGALPUR AND ITS DISTRIBUTION TO CARD-HOLDERS OF THE TOWN.

*11. **Mr. RASH BIHARI LAL:** Will the Hon'ble the Minister in charge of the Supply and Price Control Department be pleased to state—

(*a*) whether it is a fact that some cloth confiscated to Government are lying undisposed at Bhagalpur;

(*b*) if the answer to clause (*a*) be in the affirmative, whether Government propose to take steps to get them distributed amongst the card-holders of the town ;

(*c*) whether it is a fact that many card-holders for cloth in the town of Bhagalpur have not got their full quota of cloth for the last five or six months ;

(*d*) whether it is a fact that under the existing system of distribution of cloth in the muffasil area of Bhagalpur majority of people do not get cloth at all ;

(*e*) whether it is a fact that bales of cloth sent to Colgong in the district of Bhagalpur area are always found to contain less cloth than the quantity billed out and the dealers are on this account allowed to suffer loss for some shortege each time ?

**The Hon'ble Dr. ANUGRAH NARAYAN SINHA:** (*a*) The reply is in the affirmative.

(*b*) The cloth is being sent out for distribution among the card-holders.

(*c*) The reply is in the negative.

(*d*) The reply is in the negative

* In the absence of the questioner, the answer was given at the request of Mr. Satish Chandra Banerjee.

**The Hon'ble the Speaker :** मुहम्मद अब्दुल गनी साहब अपने कटमोशन को उठाना नहीं चाहते हैं। इसलिए मैं इस कटमोशन को हाउस के सामने पेश करता हूँ।

**The Hon'ble the Speaker :** The question is :

That the provision of Rs. 5,973/- for "Agricultural Experiments and Research scheme for the provision of Soil E tension Service" be-reduced by Re. 1/-.

The motion was negatived.

DETAILS OF THE SCHEME REGARDING AGRICULTURE DISTRICT STAFF—ENGINEERING STAFF

**Mr. Muhammad Abdul Ghani :** Sir, I beg to move :

That the provision of Rs. 39,033/- for "Agriculture District staff–Engineering staff" be reduced by Re. 1/-

* **Mr. Bir Chandra Patel:** गनी साहब यह जानना चाहते हैं कि detail (विस्तृत विवरण) क्या है ? पहले आप जानकारी (Information) चाहते हैं फिर उसपर बहस हो।

**The Hon'ble the Speaker:** मैं वह तरीका नहीं चाहता हूँ।

**Mr. Bir Chandra Patel:** गनी साहब जानकारी (Information) चाहते हैं। बिहार सरकार ३४ लाख रुपया पांच वर्ष में खर्च करना चाहती है। सरकार "अधिक अन्न उपजाओ" इस आन्दोलन को सफल बनाने के लिए जितना हो सके उतना tub-ewell लगवाना चाहती है। इस काम को करने के लिए गवर्नमेंट का एक खास डिपार्टमेंट है। जिसके लिए चार एडीशनल अफसर रखे गये हैं। उनके जरिये यह काम किया जा रहा है।

**The Hon'ble the Speaker.** क्या यह अधिक अन्न उपजाओ स्कीम के मातहत की चीज है ?

**Mr. Bir Chandra Patel :** युद्धोत्तर विकास स्कीम भी इसमें है। इसके काम का सिलसिला यह है कि सारे सूबे के लिये जहां तक सिंचाई और जरायत का सवाल है, एक ऐग्रिकल्चरल इंजिनियर रखा गया है। उसके अन्दर चारों रेंजों में चार इन्जिनियर रखे गये हैं। ये इंजिनियर जहाँ माइनर इरिगेशन के मातहत ट्यूब-वेल लगाना होगा, उसकी जांच करेंगे और उसके लगाने का प्रबन्ध करेंगे। इसके लिये पांच सालों के अन्दर ३४ लाख रुपया गवर्नमेन्ट ने खर्च करने का इरादा किया है। ट्यूब-वेल लगाने का हिसाब यह है कि आधा खर्च गवर्नमेन्ट देगी और आधा खर्च जिसके यहाँ ट्यूब-वेल लगेगा वह देगा। आधा जो गवर्नमेंट देगी उसमें आधा युनियन गवर्नमेंट देगी और आधा प्रान्तीय गवर्नमेंट देगी। इसलिये यह मांग पेश की गई है।

*Speech not corrected by Hon'ble Members.

**Sardar Harihar Singh :** मैं जानना चाहता हूँ कि कब से यह प्रोग्राम जारी हुआ है और कहीं ट्यूब वेल लगा है या नहीं।

**Mr. Bir Chandra Patel:** कृषि विभाग की तरफ से अभी तक कहीं नहीं लगाया गया है ।

**The Hon'ble the Speaker:** स्टेटमेन्ट के १४ वें पन्ने पर लिखा हुआ है कि ७५ ट्यूब वेल ८ इंच के, ५०—५ इंच के, और ६०—१० से १२ इंच के रहेंगे। क्या यह सब रुपया इतने ही ट्यूब वेल के लिये है ? सिफ २१५ ट्यूब वेल ही में यह सब खर्च होगा।

**Mr. Bir Chandra Patel:** नहीं, इतना खर्च तो पांच साल में होगा। Ultimate Scheme का यह खर्च है।

**The Hon'able the Speaker:** रुपये की बात नहीं है। इतने रुपये में कितने ट्यूब वेल लगेंगे ।

**Mr. Bir Chandra Patel:** पांच सालों में कितने ट्यूब वेल लगेंगे यह तो Boring staff बतायेगा ।

**Sardar Harihar Singh :** एक महीने में कितने ट्यूब वेल लगायेंगे।

**Mr. Bir Chandra Patel :** I think the hon'ble member should have given notice of a cut motion.

**Hon'ble the Speaker :** The hon'ble member may proceed with his speech.

आप को जो कुछ कहना है कह जाइये।

**Mr. Bir Chandra Patel:** गनी साहब सिलसिला जानना चाहते थे कि काम कैसे होता है। यह तो मैंने ऊपर बता दिया है कि एक ऐग्रीकल्चर इन्जिनियर है जिनकी मातहत स्टाफ है। जब कोई ट्यूब वेल लगाने की दरखास्त देता है तो उसकी जांच होती है और खर्च का जो सिलसिला मैंने बताया उसी हिसाब से काम होता है। मगर अभी तक एक भी ट्यूब वेल नहीं लगाया जा सकता है। वजह इसकी यह है कि ट्यूब वेल लगाने में पाइप की जरूरत होती है। इसके लिये भारत सरकार से खतो-किताबत सालों से हो रही है। भारत सरकार का कहना है कि छ इं० से अधिक डाइमीटर की पाइप नहीं है और फिलहाल इन्तजाम हो सकता है। बहुत कोशिश करने पर ३ इं० डाइमीटर की पाइप अभी हाल से आई है इसी से जहां तक होगा लगाया जायेगा। मगर जरूरत ६ इंच डाइमीटर से ज्यादा की है।

**Mr. Muhammad Abdul Ghani :**

ڈیا آنریبل ممبر یہ بتا سکتے ہیں کہ ڈین انچ پائپ کو اگر سو فٹ یا ڈیڑ سو فٹ تک bore کونا پڑے تو اسکا cost کتنا ہوگا -

* **Mr. Bir Chandra Patel:** इसकी जानकारी के लिये आपको ऐग्रीकल्चर इन्जनियर के आफिस में जाना चाहिये। वहां आपको मालूम हो जायेगा कि कैसी पाइप कहां लगेगी। इसका जवाब गवर्नमेन्ट नहीं दे सकती है।

**Sardar Harihar Singh:** सदर साहब, इसके बारे में एक भुक्तभोगी की हैसियत से मैं भी कुछ जानकारी रखता हूँ। माननीय मिनिस्टर साहब तो गैरहाजिर हैं मगर पार्ल्यामेंटरी सेक्रेटरी साहब मौजूद हैं, उन्हीं के सामने उसे रख देना चाहते हैं। मैंने अपनी खास जमीन में एक ट्यूब वेल लगाने के लिये करीब एक साल हुआ दरखास्त दी। दरखास्त देने के १५ दिनों बाद एक जवाब मिला कि यह सामान नहीं है, वह समान नहीं है। उसके बाद दो-दो महीने पर चिट्ठी आती रही। आखिर में यह खबर दी गई कि सितम्बर महीने में लगेगा। अभी तक ट्यूब वेल नहीं लगा मालूम होता है कि सितम्बर नहीं आया। हमने सब का दरवाजा खटखटाया मगर बेकार ही खटखटाया। अभी दो-तीन महीने हुआ उस मुहकमे के कोई अफसर सिद्दीकी साहब हैं, उनका खत मिला की हम फरवरी में आपके पास आयेंगे। थोड़े दिनों के बाद खत आता है कि फिलहाल नहीं आ सकेंगे जब फुरसत मिलेगी तो आऊँगा। यही तो हालत है।

हमें खुशी है कि गवर्नमेन्ट ने कबूल कर लिया है कि आज तक एक भी ट्यूब वेल सर्वे में नहीं लगा है। क्या गवर्नमेन्ट बतलायेगी कि कितने लोगों ने इसके लिये दरखास्त दी है। हमलोगों को अपने चुनाव क्षेत्रों में दिक्कत होती है। लोग इन बातों के बारे में पूछते हैं। हम कहां तक झूठ बोलते रहें। हाउस को याद होगा कि रांची सेशन में राहट की चर्चा हुई थी। रांची से लौटते ही हमने राहट के लिये रुपया जमा कर दिया था। तभी से इन्तजारी किया। पाच-सात रोज हुआ कि राहट मिल गया। स्पीकर साहब, जब हमारी यह हालत है तो औरों की क्या हालत होगी, ईश्वर ही जानता होगा।

हां, हमको खबर मिली है कि चोर बाजारी से आसानी से काम हो जाता है। ऐग्रीकल्चर इन्जिनियर साहब इन्तजाम कर सकते हैं। मुझसे कहा गया है कि अगर आप किसी दोस्त के नाम में लेना चाहें तो काम जल्दी होगा। इन्जिनियर साहब तुरन्त इन्तजाम कर देंगे, हां कुछ पैसे ज्यादा लगेंगे। मगर ऐग्रीकल्चर ताज्जुब है कि गवर्नमेन्ट को चीज नहीं मिलती है और चोरबाजारी में सब कुछ मिलता है।

---

* Speech not corrected by the Hon'ble Member.

इसलिए हम गवर्नमेन्ट का ध्यान इस तरफ आकर्षित करना चाहते हैं कि यह महकमा दोजख की चीज हो गयी है, इसके आमूल परिवर्तन (overhauling) की जरूरत है। गवर्नमेन्ट एक कमिटी बना दे जो देखे कि खाली रुपया ही दिया जाता है, व्यवस्था ही की जाती है या हमलोगों के फायदे की भी कोइ चीज होती है। जो लोग अधिक अन्न उपजाना चाहते हैं उनको कुछ नहीं देते। जो देते हैं वह इस डिपार्टमेंट के लोगों का जेब भरने के लिए, चोरबाजारी (Black marketing) करने के लिए यह तो हमलोगों की हालत है। पार्लियामेन्टरी सेक्रेटरी कहते हैं कि ऐग्रीकल्चरल इन्जीनियर के पास जाओ। लेकिन अपना अनुभव तो यह कहता है कि किसी भी अफसर के पास जाइए कुछ फायदा नहीं हैं। ऐसी हालत में हम यह व्यर्थ समझते हैं कि जनता का रुपया इस फालतू काम में खर्च किया जाय।

**Mr. Purusottam Chohan:** सभापति जी, पार्लियामेण्टरी सेक्रेटरी साहब का ध्यान मैं इस ओर आकर्षित करना चाहता हूँ कि पाइप मिलने की जो दिक्कत है वह कन्ट्रोल को लेकर है। हमको तो ताज्जुब होता है यह सुन कर कि पाइप नहीं मिलता है। यह ठीक है कि कन्ट्रोल वाले पाइप को first priority देना चाहिये। लेकिन जब और इन्डस्ट्रीज को पाइप मिल सकता है तब हमारी बिहार गवर्नमेंट को क्यों नहीं मिल सकता है? आप जानते होंगे कि हजारों लाखों पाइपों की मिलिटरी की ओर से नीलामी (Military auction) हुई थी तो कोई खरीदने वाला नहीं मिलता था। क्यों नहीं उस वक्त हमारी बिहार गवर्नमेन्ट ने अपना प्रतिनिधि (Representative) भेज कर वहां से खरीदा?

**Mr. Prabhunath Sinha:** आपने गवर्नमेण्ट को खबर क्यों नहीं दी?

**Mr. Purusottam Chohan:** हम नहीं जानते थे कि बिहार गवर्नमेण्ट को नहीं मिलता है। आज भी तीन इंची, चार इंची और ६ इंची पाइप मिलते हैं, लोगों ने खरीदा है और अभी भी परमिट पड़ा हुआ है। मुझे ताज्जुब होता है कि जब एक व्यक्ति (individual) को मिल सकता है तब हमारी बिहार गवर्नमेण्ट को पाइप मिलने में इतनी दिक्कत क्यों है। आजकल तो कलकता का बाजार पाइप से flooded हो गया है। कोई खरीदनेवाला नहीं है। कोई व्यापारी वहां जाता है तो खबर लाता है कि वहां बाजार में पाइप इतना है कि कोई खरीदनेवाला नहीं मिलता है। उनके हाथ में गवर्नमेण्ट की ओर से खरीदने का शिड्यूल रहता है तो इसका मतलब यह नहीं है कि कन्ट्रोल रेट से न मिले तो खरीदा ही न जाय। कलकत्ता के बाजार में जो एसोसियेशन है उसके जरिये भी मिल सकता है। मैं इस तरफ पार्लियामेण्टरी सेक्रेटरी का ध्यान दिलाना चाहता हूँ। पब्लिक मारकेट में भी कोशिश कीजिए। लाखों लाख की

दरकार होती है तो मिल सकता है और इतना थोड़ा नहीं मिलता यह ताज्जुब की बात है।

*Mr. Prabhunath Sinha: rose to speak.*

**The Hon'ble the Speaker:** वक्त कम है इसलिए लंच के बाद बोलियेगा।

[Interval for lunch]

**Mr. Prabhunath Sinha:** माननीय स्पीकर साहब, अभी मौलवी गनी साहब के कट मोशन पर बहस हो रही है और मैंने अपने से पहले बोलनेवाले माननीय मेम्बरों की स्पीचें सुनी। मैं समझता हूँ कि इसमें कोई शक नहीं कि आज जो दिक्कत सब डिपार्टमेन्ट के साथ है वह एग्रीकल्चर डिपार्टमेन्ट के साथ भी है। नौर्थ बिहार में लोगों से यह कहा गया रुपया जमा करो और इनार बनाओ,कोयला ईंटा पकाने के लिए मिलेगा। लोगों ने ईंट बनायी लेकिन कोयला नहीं मिलने के कारण बरसात में सब ईंटें गल गये। इस तरह का एक दो cases नहीं हैं; बल्कि पचासों और सैकडों है। इसके अलावे दूसरी दिक्कत यह देखने में आयी है कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेन्ट के और खास तरह से grow more food department के काम कलक्टर या एस० डी० ओ० के मार्फत होता था और उनके पास काफी अफसर नहीं थे। उनके यहाँ किसी अफसर को अपने काम के साथ साथ इस काम में लगा दिया जाता था। अपने काम के बाद जो समय बचता था उसमें वे कुछ काम कर लेते थे।

सेक्रेटेरियट के इंजिनियर के बारे में अभी सरदार साहब ने जो कुछ कहा है अगर वह कुछ भी सही हो, उसमें कुछ भी substance हो तो गवर्नमेंट को इस मामले में उस अफसर के खिलाफ जांच कर strong action लेना चाहिए। इन सब बातों के होते हुए भी इधर हमारी मिनिस्ट्री ने इस मामले में कुछ कार्रवाई की है और इसके लिए कुछ अफसर जिनके नाम पब्लिक सर्विस कमीशन की ओर से आये थे, उनको Gazetted officer के rank में बहाली की है। करीब दो महीने हुए उनकी सब जगह posting हुए है। अगर अब उनको materials supply हुए तो हम समझते हैं कि वे लोग अच्छे काम करनेवाले बहाल हुए हैं और उम्मीद है कि वे लोग अच्छी तरह से काम करेंगे जिससे प्रान्त में संतोष (satisfaction) होगा। लेकिन इसके साथ ही साथ मैं इस बात को कहना चाहता हूँ कि अगर कोयला,सिमेंट वगैरह सामान मिलने का प्रबन्ध सरकार की ओर से नहीं हुआ तो इनलोगों पर जितना खर्च होगा, इनकी सारी मिहनत, सारा दौड़-धूप और सारी स्कीम बेकार हो जायेगी। इधर तो Eletric के जरिए Irrigation का काम हो रहा है, लेकिन गंगा उसपार

ओ० टी० रेलवे में Wagon नहीं मिलने से कोयला मिलने में बड़ी दिक्कत है और इससे काम नहीं हो रहा है। दो-तीन वर्षों से Grow more food department की ओर से यह बराबर कहा जाता है कि अब चीजें मिलेंगी, यह काम बहुत जरूरी है और इसको चलाना चाहिए। लेकिन आखिर में लोगों के रुपया जमा करने पर भी न ईंट मिलते हैं और न सिमेंट मिलता है।

**The Hon'ble the Speaker :** Tube wells में भी ईंटे की जरूरत होती है ?

**Mr. Prabhunath Sinha :** सिर्फ ट्यूब-वेल ही तो नहीं है।

**The Hon'ble the Speaker :** यह कट-मोशन तो ट्यूब-वेल के लिए है।

**Mr. Prabhunath Sinha :** उसके लिये भी तो platform बनाना पड़ता है और इसके लिए ईंट सिमेंट की जरूरत पड़ती है।

**The Hon'ble the Speaker:** ईंटे की जरूरत पड़ती है तो कह सकते हैं।

**Mr. Prabhunath Sinha :** मुझे यही कहना है कि इस departmen में सिर्फ खराबियां ही हैं,ऐसी बात नहीं है। Defects होते हुये भी इधर दो-तीन महीने से देखा जाता है कि इस department का काम बहुत active तरीके से शुरू किया गया है और अगर इसी तरह जारी रहा और अगर इसी तरह से काम होता रहा और चीजों की supply होती रही तो यह department अच्छा काम करेगा। हमको इतना ही कहना था।

**Mr. Jagganath Singh :** I would like to say just a word. Sardarji has correctly said that this department has been of no help to the agriculturists of this province who are anxious to increas the food production of the province. As a matter of fact, the very admission by the Parliamentary Secretary that not a single tube-well could be constructed up till now is a very sad commentary on the working of this department. From my own experience, I can say that I personally applied for a open boring for which no 6" tubes are needed, more than a year ago; money was deposited and an agreement was completed, but still we are tired of writing to the department letters after letters for the undertaking of the work: they are only sending evasive replies and no action has been taken. Thus we are not in a position to justify the action of this department before our constituents in our respective areas. This Agricultural Engineering section

needs over-haul and I would suggest that a committee should be appointed to go into the working of this department and to find out way sand means for improving matters. Unless this is done, the Grow More Food campaign will not work successfully. I again appeal to Government to re-examine the working of this department and take effective measures fordoing good to the tenantry.

**The Hon'ble Mr. Ram Charitra Sinha :** The Agriculture Department has appointed a Committee consisting of 48 members to advise Government on question about agriculture.

**The Hon'ble the Speaker :** The department should therefore, be rightly advised, and there should be no complaint against a department which is being advised by so many hon'ble members.

**Mr. Jagat Narain Lal :** The Hon'ble Minister for Irrigation says that a Committee has been appointed. It has been appointed only the other day and the present complaint relates to a period before that date.

**The Hon'ble Mr. Ram Charitra Sinha :** But the hon'ble member says that a Committe should be appointed.

* **Mr. Bir Chandra Patel:** सभापति जी, मैं इस सभा के मेम्बरों को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इतनी बड़ी दिलचस्पी इस महकमें के बारे में दिखलाई है। आमतौर से इतनी दिलचस्पी गवर्नमेन्ट के डिपार्टमेंट पर हमारे मेंम्बर लोग नहीं दिखलाते हैं। इसलिए कम से कम उस डिपाटमेंट के आदमी होने की हैसियत से मैं उनका शुक्रगुजार जरूर हूँ कि उनकी नजर हमारे इस डिपार्टमेंट पर पड़ रही है। उन्होंने अपनी राय, अपने ख्याल से इस डिपार्टमेंट को दी है इसलिए मैं अपने डिपार्टमेंट की तरफ से उनको यकीन दिलाता हूँ और यह बात साफ है कि गवर्नमेंट अभी तक tube well नहीं रख सकी है। लेकिन साथ ही साथ यह कह देना कि गवर्नमेंट अभी तक tube well नहीं रख सकी है यह ठीक नहीं है। माननीय सदस्यों को इसकी वजह देखना चाहिये कि जिस वजह से हमारे पास इतना स्टाफ होते हुए भी ग्रो-मोर-फुड के अफसरों के होते हुए भी.........

* Speech not corrected by the Hon'ble Member.

**The Hon'ble the Speaker:** order, order आपने अभी तक एक भी tube well नहीं लगवाया है तो किस तरह आप चालीस हजार रुपया मांग रहे हैं ? It was expected to work out the scheme by December 1947.

**Mr. Bir Chandra Patel :** हमारे पास इतना स्टाफ है।

**The Hon'ble the Speaker :** पृष्ठ-संख्या ४५ में इसका ज़िक्र तो किया ही नहीं गया है ?

**Mr. Bir Chandra Patel:** चौतीस लाख का खर्चा है वह पांच वर्ष में खर्च होगा।

**The Hon'ble the Speaker:** जब आप tube well नहीं दे रहे हैं तो आप चालीस हजार की मांग क्यों कर रहे हैं ? आपके कहने से मालूम पड़ता है कि अभी तक tube well तैयार भी नहीं है।

**Mr. Bir Chandra Patel:** जहां जहां tube well लगाया जायेगा वहां वहां छोटे छोटे कारखाने हो जायेंगे । इसका खर्च भी बहुत पड़ेगा। बड़े बड़े किसान (Agriculturist) ही इसे अपने यहां लगवा सकेंगे क्योंकि इसमें पांच छः हजार रुपये इसमें खर्च पड़ेंगे। बेचारे छोटे छोटे किसानों के पास इतने रुपये कहां है कि वे tube well लगवा सकेंगे। यह ठीक है कि रुपया रहते हुए भी, स्टाफ रहते हुए भी, लोग tube well नहीं लगवा सके इसकी दो वजह हो सकती है। एक तो यह है कि सारा का सारा स्टाफ सोया रहा हो और डिपार्टमेंट की या कैबिनेट की दिलचस्पी न रही हो। दूसरी चीज यह हो सकती है कि दिलचस्पी रहते हुए भी, और स्टाफ के रहते हुए भी कुछ नहीं बन सका हो। यह एक ऐसी चीज है कि यदि हम लोगों की जगह दूसरे लोग होते तो वे भी कुछ नहीं कर पाते। हम समझते हैं कि हमारी मजबूरी ही ऐसी ही थी कि हम tube well नहीं लगा सके। चाहे हम यहां पर हों, चाहे दूसरे लोग हों, यह गैर-मुमकिन था कि यह काम इतनी आसानी से हो सके। क्योंकि tube well बनाने के लिये पम्प की जरूरत होती हैं। जिसके लिए खुद मिनिस्टर साहेब ने दिल्ली जाकर अफसरों से contact किया था। जो आदमी इस बात को जानना चाहें वह Agriculture Depratment में जाकर दरियाफ्त कर सकता है Agriculture डिपार्टमेंट के डायरेक्टर साहब खुद जाकर इस बात की कोशिश करते रहे हैं।

**The Hon'ble the peaker:** तो आप मांग किस लिए कर रहे हैं ?

**Mr. Bir Chandra Patel:** मांग हम इसलिये कर रहे हैं कि आगे चल कर काम हो सके।

**Mr. Sharangdhar Sinha:** जब ग्यारह महीने काम नहीं हो सका तो ३ महीने में क्या काम हो सकेगा ?

**Mr. Bir Chandra Patel** यह बात साफ है कि इतने महीनों में कुछ नहीं कर सके हैं और ज्यादा ट्यूब वेल tube well नहीं लगा सके हैं। इस चीज को हमको और आपको समझना चाहिये।

**The Hon'ble the Speaker :** Are Government withdrawing this motion ?

**Mr. Bir Chandra Patel :** I do not see any necessity of doing so. I am replying to the argument that has been raised as to why no tube-well has been sunk. That does not mean that Government are withdrawing the motion.

**Sardar Harihar Singh :** जब काम नहीं हुआ तो हम वैसे क्यों दें ?

* **Mr. Bir Chandra Patel :** सरकार की तरफ से हम यह विश्वास दिलाते हैं कि इसके लिए जितनी कोशिश हो सकेगी हम करेंगे।

**The Hon'ble the Speaker :** (सरदार हरिहर सिंह की तरफ इशारा करके) उन्होंने तो कहा है कि काम हो रहा है और होगा।

**The Hon'ble Dr. Anugrah Narayan Sinha :** सभापति जी, यहां बहुत ज्यादा Confusion हो गया है जैसा कि बाबू रामचरित्र सिंह ने बताया है। मैटिरियल की कमी से या न होने से काम ज्यादा नहीं होता है। यह जो बजट पेश किया है उसमें मार्च तक जो काम होने वाला है उसी के लिए रकम रखी गयी है। इसमें बहुत ज्यादा खर्च नहीं हो सकता है गवर्नमेंट को जो खर्च का अन्दाजा है उसी की बुनियाद पर यह मांग की गई है। काम चलाने में आपलोगों की मदद और सहयोग की आवश्यकता है। ३१ मार्च १९४८ के बाद आप पूछ सकते हैं कि क्या काम हुआ और क्या नहीं हुआ ?

**Mr. Shyamnandan Sahaya :** यह तो गवर्नमेन्ट मानती है कि काम नहीं हो सका। पुराने बजह में स्टाफ वगैरः के लिये रुपया मौजूद है और काम भी नहीं हो सका तो फिर सप्लिमेन्टरी बजट में इसको क्यों रखा जाता है।

**The Hon'ble Dr. Anugrah Narayan Sinha:** पुराने वजट में कहां मौजूद है ? पुराने बजट में रहता तब तो कोई बात नही थी सप्लिमेन्टरी में क्यों रखा जाता। रुपया इसलिये रखा गया है कि काम शुरु करने में देर न हो। मान लीजिये कि ३१ मार्च के पहले ही काम शुरू करना हो तो रुपया न रहने की वजह से काम रुक जायेगा यह तो सामान मिलने पर है। अगर खर्च

* Speech not corrected by the Hon'ble members.

नही होगा तो पड़ा रहेगा। रुपया कहीं जायेगा नहीं। मनशा यही है कि काम जल्द हो। कोशिश हो रही है अगर काम शुरू हो गया तो अच्छा होगा। स्टाफ को बैठाये रखने से क्या फायदा होगा।

**The Hon'ble the Speaker:** अब तो काफी बहस हो चुकी। क्या आप इसको उठाना चाहते हैं ?

**Mr. Muhammad Abdul Ghani :**

پارلیامنٹری سکریٹری کے طرف سے جواب تو کافی ملا ھے اس سے معلوم ھوتا ھے کہ ۲۰۷۱ روپیہ کی رقم اسٹاف کے لئے چاھتے ھیں - مگر ڈیمانڈ میں یہ لکھا ھوا ھے کہ Tube well جسکے لئے بڑی مجبوری ظاھر کی ھے ۳۹ ھزار کی رقم رکھی ھے تو پھر اتنی بڑی رقم رکھنے کی کیا ضرورت تھی ۔

**The Hon'ble the Speaker:** आपको बताया गया है कि पांच वर्षों में ३४ लाख खर्च होगा और शुरू में ३६ हजार खर्च होगा।

**The Hon'ble Dr. Anugrh Narayan Sinha :** अगर काम नहीं होगा तो रुपया बचा रहेगा, रुपया कहीं जाता नहीं है।

**Mr. Muhammad Abdul Ghani :**

جتنی رقم یہاں رکھی گئی ھے اس سے معلوم ھوتا ھے کہ روپیہ بچ جائیگا میری غرض کہنے کی ھے کہ آپنے بجٹ میں اتنا رقم جو provide کیا ھے جسکی ضرورت نہیں ھے اس provision سے معلو ھوتا ھے کہ saving ھوجائیگا - اگر گورنمنٹ ھر جگہ اس قسم کا provision کرے اور سوچ لے کہ بچ جائیگا اگر خرچ نہیں ھوگا تو اس قسم کے item بہت fluctuate کر جائیگا تو گورنمنٹ اتنا روپیہ کہاں سے مہیا کریگی - اور یہ بھی معلوم ھوا ھے - کہ جو اسکیم انھوں نے دیا ھے اسکے لئے materials نہیں ملرھاھے اگر آپکو اس قسم کی مجبوری ھے تو آپ اس اسکیم کو دبادیں - یہی میری گزارش ھے اب جیسی گورنمنٹ کی مرضی ھو ویسا کرے ۔

**The Hon'ble the Speaker :** The question is :

That the provision of Rs. 39,033/- for "Agriculture—District staff—Engineering Staff" be reduced by Re. 1/-

The motion was negatived.